भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1976
शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2019 का उत्तर दिए जाने के लिए

मछुआरों हेतु कम लागत के उपकरण

1976. श्री चन्द्रशेखर बेल्लाना:
श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः
श्री वाई°एस° अविनाश रेड्डीः

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मछुआरों को आपदा-संबंधी चेतावनी देने और ज्यादा मछली भंडार वाले स्थानों की पहचान करने जैसी जानकारी देने के एक कम लागत वाले उपकरण को प्रचालित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त उपकरण को 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्थानीय स्तर पर विनिर्मित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार मछुआरों को उक्त उपकरण निःशुल्क/अत्यधिक राज सहायता-प्राप्त दर पर प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) जी, हां ।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्त निकाय, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस) ने उपग्रह के द्वारा मछुआरों को संभावित मत्स्य क्षेत्र की परामर्शिकाएं, समुद्र की दशा का पूर्वानुमान लगाने, ऊंची लहरों की चेतावनियां देने, सुनामी पूर्व चेतावनी देने, विभिन्न तटीय स्थानों पर मछली बाजारों की मूल्य सूचना आदि देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से एक प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली में उपग्रह के माध्यम से भेजी गई सूचना को प्राप्त करने के लिए जेमिनी (नौचालन और सूचना के लिए गगन समर्थित मेरिनर उपकरण) नामक एक उपकरण है। जेमिनी की इस रेंज में संपूर्ण भारतीय महासागर क्षेत्र शामिल है।

(ग) जी, हां। जेमिनी रिसिवर हाथ में लिया जाने वाला उपकरण है, जिसे इंकॉइस और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार के निर्देशों पर परीक्षण और प्रदर्शन के लिए भारत में बैंगलौर की एक फर्म द्वारा तैयार किया गया है। इंकॉइस ने उपग्रह के संदेशों को नक्शों और पाठ में परिवर्तित करने के लिए जेमिनी एप को निरूपित एवं विकसित किया है । इस तरह के उपकरण के निर्माण की तकनीक किसी भी इच्छुक विनिर्माता के लिए उपलब्ध है।

(घ) इंकॉइस/पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास मछुआरों को ऐसे उपकरण के वितरण के लिए अधिदेश एवं बजट उपलब्ध नहीं है। तथापि, इंकॉइस ने शुरुआत में संबंधित राज्य मात्स्यिकी विभागों के जरिए लगभग 50,000 पंजीकृत मछली जलयानों को ये उपकरण वितरित करने/राज सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड/मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार को एक स्कीम प्रस्तुत की है।

*****